Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-16, अंक-23 01-15 दिसंबर, 2021 (पाक्षिक) ₹20

भाजपा सरकार देश के जवानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध

प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया

जनजातीय गौरव दिवस

देश जनजातीय परंपराओं और शौर्य गाथाओं को और अधिक सार्थक एवं भव्य पहचान देगा

रुद्रपुर (उत्तराखंड) में एक प्रदेश सांगठनिक बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, मुंबई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय का दौरा करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

मुंबई में असम के भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और साथ में असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य वरिष्ठ नेतागण

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

वाराणसी में उत्तर प्रदेश के भाजपा विधानसभा प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

मुनाकोट (उत्तराखंड) में 'सैनिक सम्मान यात्रा' का शुभारंभ करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी व अन्य

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन जिया, अपनी संस्कृति और देश के लिए प्राणों का परित्याग किया

पिछले दिनों भारत सरकार ने घोषणा की कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को रांची में भगवान बिरसा मुंडा...

08 पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश का गौरव है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन...

12 'उत्तराखंड की जनता ने मिशन वाले को आगे बढ़ाने और कमीशन वालों को घर बैठाने का मन बना लिया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड में...

14 प्रदेश की जनता को जिन्ना-आजम-मुख्तार नहीं, जनधन-आधार-मोबाइल चाहिए : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह उत्तर प्रदेश...

32 गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेलवे का गौरव भी जुड़ गया है: नरेन्द्र मोदी

गत 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में रेलवे की विभिन्न...

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन

हमने कृषि विकास और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी: नरेन्द्र मोदी 11

वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 19

श्रद्धांजलि

दार्शनिक व प्रखर राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो 21

लेख

जन-मन को भाती–मन की बात / **शिवप्रकाश** 24

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन: विश्व को भारत का उपहार / **राम प्रसाद त्रिपाठी** 28

गति शक्ति विभागों के आपसी दूरी को कम करके उनके बीच समन्वय स्थापित करेगी / **विकास आनन्द** 29

'पीपल्स पद्म' पुरस्कार: गौरव को पुनर्स्थापित किया / **विपुल शर्मा** 30

अन्य

भाजपा महाराष्ट्र में 'महाविकास अघाडी' सरकार को उखाड़ फेंकेगी 13

अप्रैल-अक्टूबर में भारत का व्यापारिक निर्यात 2019 की तुलना में 54.5% बढ़कर 232.58 बिलियन डॉलर रहा 16

फिर से खुला 'श्री करतारपुर साहिब' कॉरिडोर 18

गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 'आईएनएस विशाखापत्तनम' राष्ट्र को समर्पित 22

प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी की पहली किस्त हस्तांतरित की 23

किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है: नरेन्द्र मोदी 26

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ. प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

कोई काम, कोई पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता है, यह 'जन धन' के परिणाम में भी दिख रहा है। कोरोना के कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई पर भारत का गरीब टिका रहा, तो ये जन धन अकाउंट की ताकत थी।

जगत प्रकाश नड्डा

कांग्रेस ने अपने 70 साल में सिर्फ वोट लेने के अलावा कुछ नहीं किया। लोगों को मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया होता, तो 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को करीब 10 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर (शौचालय) नहीं देने पड़ते।

अमित शाह

मोदी सरकार देश के हर गांव तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने हेतु संकल्पित है, जिससे हर व्यक्ति देश-दुनिया से जुड़ पाए। उसी दिशा में कैबिनेट ने 5 राज्यों के दूर दराज के 7287 गांवों तक 4G सेवा पहुंचाने हेतु यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए श्री नरेन्द्र मोदीजी का अभिनंदन करता हूं।

राजनाथ सिंह

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन, उत्तर प्रदेश में विकास के नए दौर के प्रतीक है। अब देश में बन रहे हाईवे और एक्सप्रेसवे सामान्य आवागमन के साथ-साथ युद्धक विमानों के लिए 'रनवे' का भी काम करने में सक्षम हो रहे हैं। यह है 'नया भारत' !

बी.एल. संतोष

तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का भाषण सुनकर आश्चर्य होता है कि ये किस तरह के लोग हैं। जो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त कर, उसके ऊपर उपदेश देते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके हाथ भाजपा कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं।

नितिन गडकरी

कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा की गई घोषणा हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गुरु नानक देवजी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर यह कदम सबको साथ लेकर देश को आगे ले जाने के उनके संकल्प को रेखांकित करता है।

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
विवाह पंचमी (8 दिसंबर)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

संपादकीय

गुरु नानक देव के 'प्रकाश पर्व' के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों के निरस्त करने के निर्णय से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अद्भुत मानवीय, लोकतांत्रिक, विश्वसनीय एवं कर्तव्यनिष्ठ चेहरा देश के सामने पुनः आया है। इस निर्णय को अनेक प्रकार से देखा जाएगा तथा विशेषकर आलोचक अपनी राजनीति को ध्यान में रखकर इसकी नकारात्मक विवेचना करने का प्रयास करेंगे, परंतु वास्तव में यह निर्णय प्रधानमंत्री को पुनः एक बार सर्वाधिक प्रभावशाली नेता के रूप में दर्शाता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने संवेदनशील पहलों से किसी भी गतिरोध का समाधान कर सकते हैं। एक प्रधानमंत्री जो सुनता है, ख्याल रखता है तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति को शक्ति देता है तथा अत्यंत विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य और संयम नहीं खोता है, इन गुणों के साथ आज देखा जाए तो वे सही अर्थों में देश के 'प्रधानसेवक' बन गए हैं तथा 'राष्ट्र सर्वोपरि' के मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं। अनेक ऐसे अवसर आए जब उन्होंने 'राष्ट्र प्रथम, पार्टी उसके बाद एवं स्वयं सबसे अंत में' के पवित्र सिद्धांत को स्वयं के उदाहरण से साकार किया है।

इन कृषि सुधारों पर देश में लंबे समय से चर्चा चलती रही है तथा अनेक किसान नेता, विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री एवं विभिन्न राजनैतिक दल अलग-अलग मंचों पर छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए इनकी वकालत करते रहे हैं। यही कारण रहा कि जिन लोगों ने बाद में इन सुधारों का विरोध किया, उनमें वे लोग थे जो वास्तव में न केवल इनकी मांग करते रहे, बल्कि संसद में जब ये विधेयक लाए गए तब इनका समर्थन किया और इन विधेयकों के पारित होने पर इनका स्वागत किया था। लक्ष्य शुरू से ही स्पष्ट था– गांव, गरीब एवं किसान के जीवन में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र का व्यापक विकास। किसान नेताओं के एक वर्ग ने जिस प्रकार का तर्कहीन, असंगत एवं जिद्दी रवैया अपनाया, उससे कांग्रेस एवं इसके सहयोगी इन महत्वपूर्ण कृषि सुधारों पर गंदी राजनीति करने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के हित के विपरीत कार्य करने के दाग से अपना दामन नहीं बचा सकते।

देश में अब तक 'कांग्रेस-कम्युनिस्ट' मॉडल का 'लोकतंत्र' चल रहा था जिसमें जनता को शासकों द्वारा 'शासित' समूह के रूप में देखा जाता है, विपक्ष को कुचला जाता है, विरोध का दमन होता है, असहमत स्वरों को दबाया जाता है, विरोधियों पर लाठी-गोली चलायी जाती है और यहां तक कि पूरे देश पर आपातकाल तक थोप दिया जाता है। इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना की है जिसके अंतर्गत विरोध के स्वर एवं विपक्ष को सुना जाता है, राष्ट्र के व्यापक हित में उन्हें समायोजित किया जाता है तथा विकट परिस्थितियों में भी अत्यंत धैर्य एवं संयम का शासन द्वारा परिचय दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आप देश में 'सहयोगात्मक संघवाद' का उदय हुआ है जिसमें विपक्ष द्वारा शासित राज्य सरकारें भी आज केंद्र से सभी प्रकार के सहयोग एवं सहायता प्राप्त कर रही हैं। आज जब उन पर पूरे देश का असीम विश्वास है तथा राष्ट्र का अजेय जनादेश उन्हें प्राप्त है, वे किसानों के एक छोटे वर्ग की बात को सुनना अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य समझते हैं और यहां तक कि कानून को वापस लेने तक का निर्णय करते हैं। जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पर लालकिले की घटना को अत्यधिक धैर्य एवं संयम से संभाला, वह श्री नरेन्द्र मोदी के लोकतांत्रिक मूल्यों पर अटूट आस्था एवं विश्वास का परिचय देता हैं।

गरीब, पीड़ित, वंचित एवं शोषित के हितों के लिए प्रतिबद्ध एक नेता के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति के आयामों को अपने असाधारण सेवाभाव, पूर्ण समर्पण एवं अद्भुत दायित्व बोध से पुनः परिभाषित किया है

गरीब, पीड़ित, वंचित एवं शोषित के हितों के लिए प्रतिबद्ध एक नेता के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति के आयामों को अपने असाधारण सेवाभाव, पूर्ण समर्पण एवं अद्भुत दायित्व बोध से पुनः परिभाषित किया है। इसका परिणाम कोविड-19 महामारी के दौरान उनके अद्भुत नेतृत्व क्षमता एवं रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ टीकाकरण के रूप में आज पूरा विश्व देख रहा है। राष्ट्रहित के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर अटूट आस्था के कारण आज वे करोड़ों देशवासियों की आंखों के तारे बन गए हैं। आज जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीरो-बजट कृषि, देश की आवश्यकतानुसार फसल उपज में परिवर्तन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है, तब इसमें कोई संदेह नहीं कि गांव, गरीब एवं किसान के कल्याण के लिए राष्ट्र निरंतर कृतसंकल्पित है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन

भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन जिया, अपनी संस्कृति और देश के लिए प्राणों का परित्याग किया

यह संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों और नायिकाओं के योगदान को दर्शाने वाली विविधता से भरी हमारी जनजातीय संस्कृति का जीवंत स्थल बनेगा

पिछले दिनों भारत सरकार ने घोषणा की कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परम्पराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी अधिक भव्य पहचान देगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवम्बर अर्थात् भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाएगा।

> यह अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले एक अलग जनजातीय मंत्रालय का गठन किया और जनजातीय हितों को देश की नीतियों से जोड़ा

श्री मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी प्रबल इच्छाशक्ति से झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। श्री मोदी ने कहा कि यह अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले एक अलग जनजातीय मंत्रालय का गठन किया और जनजातीय हितों को देश की नीतियों से जोड़ा।

प्रधानमंत्री ने देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को भगवान बिरसा मुंडा स्मारक उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय, स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायक-नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी जनजातीय संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा।

भगवान बिरसा के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा जानते थे कि आधुनिकता के नाम पर विविधता, प्राचीन पहचान और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास समाज के कल्याण का तरीका नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ ही वे आधुनिक शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे और अपने ही समाज की बुराइयों और कमियों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते थे।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य भारत की सत्ता, भारत के लिए निर्णय लेने की अधिकार-शक्ति भारतीयों के हाथों में स्थानांतरित करना है। इसके अलावा 'धरती आबा' की लड़ाई भी उस सोच के खिलाफ थी जो भारत के जनजातीय समाज की पहचान मिटाना चाहती थी।

श्री मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन जिया, अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इसलिए, वह आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावना में हमारे भगवान के रूप में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जीवन के इस छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिखा और भारत की पीढ़ियों को दिशा दी। ■

'जनजातीय गौरव दिवस' का शुभारंभ

भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिवस 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर, 2021 को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाए जाने से जुड़े समारोह की अगुवाई की। प्रारंभ में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए वर्चुअल ढंग से रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया।

श्री मोदी ने जनजातीय विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन शिक्षा का मजबूत परिसर बनाने के मिशन को जारी रखते हुए भोपाल से वर्चुअल ढंग से 7 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश के 27 जिलों में 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के निर्माण की आधारशिला रखी। इस समारोह में गणमान्यजनों, राजनीतिक नेताओं और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पूरे भारत में भारतीय आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख कदमों में से एक है और इसकी शुरुआत दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा सुलभ कराने के लिए वर्ष 1997-98 में की गई थी। वित्त वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि 50 प्रतिशत से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार ने देश भर में 452 नए विद्यालय खोलने का फैसला किया है।

जनजातीय विद्यार्थियों की आदिवासी संस्कृति और भाषा की सराहना एवं सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव (भारत @75) के तहत जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा में आवश्यक सहयोग देने के लिए लगभग 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का संकल्प लिया गया है। इनमें से बड़ी संख्या में विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले प्रति विद्यार्थी व्यय को लगभग 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये से भी अधिक कर दिया गया है, जिससे जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले प्रति विद्यार्थी व्यय को लगभग 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये से भी अधिक कर दिया गया है, जिससे जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना को जीवंत या बरकरार रखते हुए जनजातीय विद्यार्थियों की क्षेत्रीय भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय न केवल अकादमिक शिक्षा, बल्कि जनजातीय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर देते हुए जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण या बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों में छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रत्येक विद्यालय में 480 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है।

वर्तमान में देश भर में इस तरह के 367 विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है जो नवोदय विद्यालय जैसे ही हैं और जहां खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन विद्यालयों में भोजन एवं आवास निःशुल्क होने के साथ-साथ मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। ■

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश का गौरव है: नरेन्द्र मोदी

सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेस-वे पर बनाई गई 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित हुआ भव्य एयरशो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। उन्होंने सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेस-वे पर बनाई गई 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित एयरशो का भी अवलोकन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि तीन साल पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करते समय उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन वे उसी एक्सप्रेस-वे पर सीधे लैंड भी करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा, यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है, यह एक्सप्रेस-वे एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए है, यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं का प्रतीक है, यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में संकल्पों को पूरा करने का एक प्रमाण है और यह उत्तर प्रदेश का गौरव और अपने आप में अनूठा है।

श्री मोदी ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही जरूरी है। कुछ क्षेत्र विकास में आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्षेत्र दशकों पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह असमानता किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से और उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास की इतनी संभावनाएं होने के बावजूद देश में हो रहे विकास से ज्यादा फायदा नहीं हुआ।

श्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें जिस तरह से लंबे समय तक चलीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

श्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम और उत्तर प्रदेश के लोगों की सराहना की। उन्होंने उन किसानों को भी धन्यवाद दिया, जिनकी भूमि का इसमें उपयोग किया गया है। उन्होंने इस परियोजना में शामिल श्रमिकों और इंजीनियरों की सराहना की।

श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी देश की समृद्धि। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण करते समय इस बात को भी ध्यान में फाइटर जेट्स की इमरजेंसी लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने दशकों तक देश में रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे की अनदेखी की।

श्री मोदी ने अफसोस व्यक्त किया कि गंगा जी और अन्य नदियों से युक्त इतने बड़े क्षेत्र के बावजूद 7-8 साल पहले तक कोई विकास नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि 2014 में जब देशवासियों ने उन्हें देश की सेवा करने का अवसर दिया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी। उनका यह सपना है कि गरीबों को पक्के घर मिलें, गरीबों के घर में शौचालय हों, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे, जो यहां किए जाने जरूरी थे।

पहले की सरकारों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी, उसने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार द्वारा यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, विकास में भेदभाव किया जा रहा है, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा जा रहा है, यूपी के लोग ऐसा करने वाली सरकार को हमेशा-हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे।

श्री मोदी ने पूछा कि कौन भूल सकता है कि यूपी में पहले कितनी बिजली कटौती होती थी, कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून-व्यवस्था की क्या हालत थी और कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में यूपी में चाहे पूर्व हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है और हजारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है।

साकार हो रहा है उत्तर प्रदेश के विकास का सपना

श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से अब उत्तर प्रदेश के विकास का सपना साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स स्थापित किए जा रहे हैं, आधुनिक शिक्षण संस्थान बनाए जा रहे हैं। कुछ ही हफ्ते पहले कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भी एक सच्चाई थी कि उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश, पहले एक दूसरे से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग-अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पूछ है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे अपार आकांक्षाओं और विकास की अपार संभावनाओं वाले शहरों को लखनऊ से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छे राजमार्ग पहुंचते हैं, वहां विकास की गति बढ़ती है, रोजगार का सृजन तेजी से होता है।

यह एक्सप्रेस-वे तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा, यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है, यह एक्सप्रेस-वे एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए है, यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं का प्रतीक है

श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है, यूपी के हर कोने को एक-दूसरे से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने

341 किलोमीटर लंबा है पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की लम्बाई 341 किलोमीटर है। यह लखनऊ-सुल्तानपुर रोड (एनएच-731) पर स्थित गांव चौदसराय, जिला लखनऊ से शुरू होता है और यूपी-बिहार सीमा से 18 किमी पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित गांव हैदरिया में समाप्त होता है। एक्सप्रेस-वे 6 लेन चौड़ा है, जिसे भविष्य में 8-लेन तक बढ़ाया जा सकता है। लगभग 22,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग— विशेष रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कहा कि यूपी में जैसे-जैसे एक्सप्रेस-वे तैयार हो रहे हैं, औद्योगिक गलियारे का काम भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास नए उद्योग लगने लगेंगे। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थित शहरों में खाद्य प्रसंस्करण, दूध, कोल्ड स्टोरेज, फलों और सब्जियों के भंडारण, अनाज, पशुपालन और अन्य कृषि उत्पादों से संबंधित उत्पादों पर काम तेजी से बढ़ने वाला है।

उन्होंने कहा कि यूपी के औद्योगीकरण के लिए कुशल कामगारों की आवश्यकता है। इसलिए कामगारों को प्रशिक्षित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इन शहरों में आईटीआई और अन्य प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर यहां रोजगार के नए अवसर लेकर आने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाएं भविष्य में अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

श्री मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति घर भी बनाता है तो पहले रास्तों की चिंता करता है, मिट्टी की जांच करता है, दूसरे पहलुओं पर विचार करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है, जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगीकरण के सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों-साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही।

श्री मोदी ने कहा कि आज यूपी में डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के आम लोगों को अपना परिवार समझकर काम कर रही है। नए कारखाने लगाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दशक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है।

आज यूपी में डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के आम लोगों को अपना परिवार समझकर काम कर रही है। नए कारखाने लगाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इस दशक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है

श्री मोदी ने कोरोना टीकाकरण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने भारत में बनी वैक्सीन के खिलाफ किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं देने के लिए यूपी के लोगों की सराहना की।

उत्तर प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार दिन-रात काम कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार दिन-रात काम कर रही है। कनेक्टिविटी के साथ-साथ यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल 2 वर्षों में यूपी सरकार ने लगभग 30 लाख ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा पेयजल कनेक्शन प्रदान किया है और इस वर्ष डबल इंजन सरकार लाखों बहनों को उनके घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से राष्ट्र निर्माण में लगे रहना हमारा कर्तव्य है, हम वही करेंगे। ■

हमने कृषि विकास और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी: नरेन्द्र मोदी

तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य यह था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले

गत 19 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को संबोधित किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि डेढ़ साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है।

श्री मोदी ने कहा कि अपने पांच दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। इसीलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों की हालत सुधारने के लिये हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतर किस्म के बीज के साथ ही नीम कोटेड यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाओं से भी किसानों को जोड़ा।

श्री मोदी ने बताया कि किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिये भी अनेक कदम उठाये गये हैं। देश ने अपने ग्रामीण बाजार अवसंरचना को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बढ़ाया ही, अपितु रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाये। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं।

> हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए

श्री मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाभियान में देश में तीन कृषि कानून लाये गये थे। इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत तथा उपज बेचने के लिये ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिलें। उन्होंने कहा कि वर्षों से यह मांग देश के किसान, कृषि विशेषज्ञ और किसान संगठन लगातार करते रहे हैं। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया है। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाये गये। देश के कोने-कोने में अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत और समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने इस कदम का समर्थन करने के लिये संगठनों, किसानों और लोगों को आभार व्यक्त किया।

सरकार नेक नीयत से कृषि कानून लेकर आई

श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी।

उन्होंने आगे कहा कि इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया।

श्री मोदी ने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।

पवित्र गुरुपर्व के वातावरण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन किसी को दोष देने का नहीं है, किसानों के कल्याण के लिए काम करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का दिन है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। श्री मोदी ने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ■

'उत्तराखंड की जनता ने मिशन वाले को आगे बढ़ाने और कमीशन वालों को घर बैठाने का मन बना लिया है'

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड में 15 एवं 16 नवंबर 2021 को दो दिवसीय प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकें कीं। श्री नड्डा ने 15 नवंबर को वीर जवानों की भूमि सवाड़, देवाल (चमोली) से उत्तराखंड की राज्यव्यापी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और उत्तराखंड की भाजपा सरकार देश के जवानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। श्री नड्डा ने शहीद सम्मान यात्रा में वीर शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट, विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह, सहित कई सांसद, विधायक, उत्तराखंड सरकार में मंत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वीर जवानों के परिवार और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने उत्तराखंड के निवासियों को इगास के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं दी और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड के वीर सपूतों ने द्वितीय विश्वववयुद्ध और उसके बाद पेशावर की लड़ाई हो, 1962 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या कारगिल की लड़ाई, देश के लिए हर संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान किया है और इन सभी संग्राम में सवाड़ गांव के वीर सपूतों ने अपनी वीरता से न केवल उत्तराखंड, बल्कि देश और पूरी दुनिया में यहां का नाम रौशन किया है। उत्तराखंड की वीर भूमि के कण-कण में देशभक्ति, वीरता और देवत्व गुण समाहित है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री गणेश जोशी को शहीद सम्मान यात्रा के आयोजन के लिए हार्दिक साधुवाद दिया।

ज्ञात हो कि शहीद सम्मान यात्रा आज से शुरू होकर 07 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लगभग 1734 वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी एकत्रित की जायेगी और उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम में इसका उपयोग किया जाएगा। सभी शहीदों को ताम्र पत्र देकर उनके कृतित्व और योगदान को याद किया जाएगा। यह शहीद सम्मान यात्रा राज्य के सभी 13 जिलों और 70 ब्लॉक से होकर गुजरेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि शहीद सपूत किसी एक परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। देश के सभी परिवार वीर शहीदों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं पढ़ाई की व्यवस्था के साथ-साथ वीरांगनाओं के कल्याण के लिए भी योजनायें चलाई जा रही हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि देहरादून से दिल्ली को जोड़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी एलिवेटेड रोड का निर्माण करा रहे हैं जिससे दिल्ली-देहरादून की दूरी दो से ढाई घंटे रह जायेगी। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने गेस्ट शिक्षकों की सेलरी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की है, सरकारी डॉक्टर्स की संख्या को 1800 से बढ़ाकर 2300 किया है, हर जिले में एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थापित किया जा रहा है, इसकी पहल भी हमारी सरकार ने की है।

शहीद परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं पढ़ाई की व्यवस्था के साथ-साथ वीरांगनाओं के कल्याण के लिए भी योजनायें चलाई जा रही हैं

विपक्ष पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने उत्तराखंड की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मिशन वाले को आगे बढ़ाने और कमीशन वालों को घर बैठाने का मन बना लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में जब अधिकारी विकास के लिए टिप्पणी वाला नोट आगे बढ़ाते थे तो मंत्री रुपये वाला नोट समझने लगते थे क्योंकि नो वर्क विदाउट नोट, नो वर्क विदाउट कमीशन इनका पर्याय बन चुका था। लंबी अवधि तक कांग्रेस के कारण देश को नुकसान सहना पड़ा। आज भी जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। आज भी कांग्रेस की सरकारों के घपले-घोटाले ही सामने आते रहते हैं। राजस्थान में किस कदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और महाअघाड़ी सरकार में किस तरह महाराष्ट्र में लूट का खेल चल रहा है, इससे पूरे देश की जनता वाकिफ है। यदि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना होगा। डबल इंजन की सरकार में ही उत्तराखंड का विकास हो सकता है। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का महाराष्ट्र प्रवास

भाजपा महाराष्ट्र में 'महाविकास अघाडी' सरकार को उखाड़ फेंकेगी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा 11 नवंबर, 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र पहुंचे और प्रदेश भाजपा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री नड्डा ने मुंबई के रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में देश भर के भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जहां देश भर के 1400 से अधिक भाजपा विधायक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए।

प्रतिभागियों से बात करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 'महाविकास अघाडी' (एमवीए) सरकार को लोकतांत्रिक तरीकों से उखाड़ फेंकेगी और तब तक हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरे के बाद श्री नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, इसके भी दीनदयालजी एक महान उदाहरण हैं। उनका 'एकात्म मानववाद' का विचार प्रत्येक मनुष्य के लिए था। जहां कहीं भी मानव सेवा और मानवता या समाज का कल्याण होगा, वहां पंडितजी के विचार प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने सभी से पंडितजी की जीवन यात्रा पर आधारित प्रबोधिनी स्थित इस संग्रहालय को अवश्य देखने का आग्रह किया।

> भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास में विश्वास करती है। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि भाजपा 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया' के माध्यम से एमवीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी

2019 में भाजपा के साथ 'धोखा' हुआ

मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अक्टूबर, 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में भाजपा को धोखा दिया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया और इसी कारण भाजपा को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा।

"2019 के विधानसभा चुनाव में जनादेश भाजपा के लिए था, लेकिन हम ठगे गए। मैं महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही तीनों सत्ताधारी दल विपक्ष में बैठेंगे और भाजपा अपने दम पर सत्ता में आएगी।"

श्री नड्डा ने आगे कहा कि इन सभी छल के बावजूद अगले साल बृहन्मुंबई नगर निगम निकाय चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "जिस तरह से मुंबई में अलग-अलग स्थानों पर मेरा स्वागत किया गया, और जो उत्साह मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, उससे पता चलता है कि आपने सभी को सबक सिखाकर आगामी बीएमसी चुनावों में भाजपा को सफल बनाने का फैसला कर लिया है। यह समय की मांग है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे वह मुंबई हो या महाराष्ट्र या देश, एक ही पार्टी है जो देश, राज्य और मुंबई को आगे ले जाने के लिए तैयार है- वह है भाजपा।"

उन्होंने कहा, "अन्य सभी दल वंशवाद के दलदल में सिमटकर रह गये हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है। कोई हिंदुत्व को लेकर आया, कोई विकास की बात करता था, और कोई अन्य मुद्दों पर आया लेकिन वे सभी दल 'मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी' तक सिमट कर रह गये हैं। अगर कोई है जो देश, राज्य या मुंबई के विकास की बात करता है, तो वह केवल भाजपा है।"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास में विश्वास करती है। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि भाजपा 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया' के माध्यम से एमवीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ■

प्रदेश की जनता को जिन्ना-आजम-मुख्तार नहीं, जनधन-आधार-मोबाइल चाहिए : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में 12 एवं 13 नवंबर को दो दिवसीय प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों में भी भाग लिया। श्री शाह ने 13 नवंबर 2021 को आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इसके पश्चात् बस्ती में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया तथा एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, बस्ती के कार्यक्रम में सांसद श्री हरीश द्विवेदी सहित कई सांसद, राज्य सरकार में मंत्री, विधायक, वरिष्ठ भाजपा नेता और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि जिस प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था ठीक न हो, वहां विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में एक समय था जब पुलिस के कर्मचारी बाहुबलियों से डरते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते ही राज्य के बाहुबली आत्मसमर्पण करने के लिए गले में पट्टी डालकर निकलते हैं कि गोली मत चलाओ।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी स्वयं उत्तर प्रदेश के काशी से चुन कर आते हैं। वे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध रहते हैं और उनकी योजनाओं को जमीन पर अक्षरशः उतारने का कार्य पिछले पांच वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी ने किया है।

सपा, बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की नीति और राजनीति होती थी, आज केवल और केवल विकास की राजनीति होती है

उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की नीति और राजनीति होती थी, आज केवल और केवल विकास की राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले राज्य की जीडीपी 10.90 लाख करोड़ रुपये थी जो आज लगभग दो गुना होकर 21.31 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% से घटकर 4.2% पर आ गया है। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज थे, आज 40 हैं। इसी तरह, मेडिकल सीटें 1200 से तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 3800 हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई है और खाद्यान्न उत्पादन में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार आने से पहले आधे-अधूरे दो एक्सप्रेस-वे थे लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से योगी सरकार में आज प्रदेश में पांच नए एक्सप्रेस-वे बने हैं। साथ ही, डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है।

समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव और मुलायम यादव सरकारों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार का अंतर स्पष्ट करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएं दी, जैसे J से जन-धन खाते, A से आधार और M से मोबाइल तो वहीं अखिलेश यादव की सपा की भी एक JAM योजना है, जिसका अर्थ है - J से जिन्ना, A से आजम खान और M से मुख्तार। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को देश के विभाजन के गुनाहगार जिन्ना में महानता नजर आती है, इसलिए चुनाव आते ही उनको जिन्ना याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के समय में जिन्ना-आजम-मुख्तार वाला JAM नहीं, जन-धन, आधार और मोबाइल वाला JAM चाहिए। जाति-पाति, दंगे, वोट बैंक व तुष्टिकरण की राजनीति ही सपा, बसपा और कांग्रेस की राजनीति की पहचान है।

आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगार के रूप में जाना जाता था, उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा को विदेशी आक्रान्तों से मुक्त करने वाले महाराजा सुहेलदेव के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाय तो यह सही मायनों में महाराजा सुहेलदेव के प्रति हमारी एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। ■

कमल पुष्प

सहयोग, समर्पण और संस्कार

भाजपा/जनसंघ कार्यकर्ताओं की कहानी #SevaSamarpan साझा करना चाहते हैं?

narendramodi.in

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक अनूठे मॉड्यूल का अनावरण

गौरवशाली अतीत की नींव पर ही एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा हमारे देश की जड़ों से जुड़ा रहा है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारा इतिहास क्या है। यही सिद्धांत हमारी अपनी पार्टी के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर भी लागू होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नमो ऐप के एक नए और अनोखे मॉड्यूल का उद्घाटन किया। ये मॉड्यूल है 'कमल पुष्प'।

कमल पुष्प एक नेक पहल है, जहां लोग भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की जीवनी से जुड़े लेख अपलोड कर सकते हैं, जिन्होंने सेवा सहयोग और संस्कार की भावना से लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

प्रधानमंत्रीजी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों के बलिदान के बारे में एक भावनात्मक भाषण दिया, जिनके अथक प्रयासों से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का निर्माण हुआ है। उन्होंने लोगों को अतीत के प्रेरक कार्यकर्ताओं के जीवन और समय का दस्तावेजीकरण करने के लिए कमल पुष्प मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

दरअसल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि यह नमो ऐप का सबसे अहम हिस्सा है और वो चाहते हैं कि हैं कि हर भाजपा कार्यकर्ता इसके लिए समय निकाले और उन कार्यकर्ताओं के प्रेरक जीवनियों को संग्रहित करे। प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर और परंपरा पर चलती है, न कि वंश या परिवार पर इसलिए आज के कार्यकर्ताओं के लिए पुराने कार्यकर्ताओं की कहानियों से जुड़ना बेहद जरूरी है।

कमल पुष्प टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक फ्जूयन (मिश्रण) है, जहां एक मोबाइल ऐप जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अतीत का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। कार्यकर्ता इस मॉड्यूल में फोटो, वीडियो, अखबार की कटिंग, लिंक अपलोड कर सकते हैं और यहां तक कि लिख भी सकते हैं।

पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित कर देने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों की निस्वार्थ सेवा को संग्रहित करने, संगठित करने और प्रसारित करने के लिए है। ■

संगठनात्मक नियुक्तियां

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 21 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक नियुक्तियां की।

श्री विनोद तावड़े को भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। श्री तावड़े अभी तक भाजपा राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे। इससे पूर्व वह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही, बिहार के श्री ऋतुराज सिन्हा और झारखंड की श्रीमती आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री, जबकि पश्चिम बंगाल की श्रीमती भारती घोष और श्री शहजाद पूनावाला को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह की ओर से जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में इन नियुक्तियों की घोषणा की गई। ■

अप्रैल-अक्टूबर में भारत का व्यापारिक निर्यात 2019 की तुलना में 54.5% बढ़कर 232.58 बिलियन डॉलर रहा

बढ़ती औद्योगिक वृद्धि, नियंत्रित मुद्रास्फीति और मजबूत सेवाओं का पुनरुद्धार

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ई-वे बिल, बिजली की खपत और जीएसटी संग्रह जैसे कई उच्च आवृत्ति संकेतकों के नवीनतम स्तरों से परिलक्षित होता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में गतिविधि के स्तर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी संग्रह अक्टूबर, 2021 में 1.3 लाख करोड़ रुपये के अपने दूसरे उच्चतम मासिक संग्रह स्तर तक पहुंच गया, जो विकास पुनरुद्धार की मजबूती को दर्शाता है। अक्टूबर, 2021 में ट्रैक्टर की बिक्री 1,15,615 इकाइयों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो सितंबर, 2021 की मात्रा की तुलना में 25% अधिक है और यह कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि का संकेत है।

वित्त वर्ष 2021-22 के अक्टूबर में लगातार सातवें महीने निर्यात के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था विकास के इंजन को तौर पर उभर रही है, यह 30 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया है। संचयी आधार पर अप्रैल-अक्टूबर में भारत का व्यापारिक निर्यात 232.58 बिलियन डॉलर रहा, जो 2019 में इसी अवधि की तुलना में 54.5% अधिक है।

अक्टूबर, 2021 में ट्रैक्टर की बिक्री 1,15,615 इकाइयों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो सितंबर, 2021 की मात्रा की तुलना में 25% अधिक है और यह कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि का संकेत है

सितंबर, 2021 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के जारी त्वरित अनुमान औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2021-22 में आईआईपी, पहली तिमाही में औसतन 121.3 से बढ़कर दूसरी तिमाही में 130.2 हो गया है। दूसरी तिमाही में भी आईआईपी अभी भी अधिक होता, किन्तु भारी मानसून के कारण खनन गतिविधियों विशेष रूप से कोयले के खनन में हुई कमी और फलस्वरूप बिजली उत्पादन में सामने आई बाधाओं के कारण समग्र उत्पादन सूचकांक में वृद्धि प्रभावित रही है।

आईआईपी में विनिर्माण सूचकांक स्थिर रहा और अक्टूबर, 2021 में विनिर्माण के लिए खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के आठ माह के उच्च स्तर 55.9 तक पहुंचने के बाद आगामी महीनों में इसमें वृद्धि की संभावना है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के 74.0 के औसत से दूसरी तिमाही में 91.7 तक पूंजीगत सामान सूचकांक में हुई त्वरित वृद्धि निवेश में एक महत्वपूर्ण सुधार को रेखांकित करती है।

वित्त वर्ष 2021-22 में खपत में हुई वृद्धि से निवेश के बढ़ने के स्पष्ट संकेत हैं क्योंकि उपभोक्ता टिकाऊ सूचकांक पहली तिमाही में 91.7 से बढ़कर दूसरी तिमाही में 121.2 हो गया, जबकि उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सूचकांक भी दो तिमाहियों में 139.1 से बढ़कर 146.9 हो गया।

अक्टूबर, 2021 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के जारी आंकड़ों से जानकारी मिलती है कि वार्षिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट अब धीरे-धीरे वित्त वर्ष 2021-22 में कम हो गई है। वार्षिक सीपीआई मुद्रास्फीति पहली तिमाही में 5.6 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत हो गई है और वित्त वर्ष 2021-22 के अक्टूबर में यह 4.5 प्रतिशत पर रहते हुए अभी भी कम बनी हुई है।

इसी तरह, उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 4.0 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 2.6 प्रतिशत और अक्टूबर में 0.8 प्रतिशत हो गई है, यह दर्शाता है कि खाद्य वितरण के आपूर्ति पक्ष में व्यवधान काफी कम हो गया है।

पीएमआई सेवाएं अक्टूबर, 2021 में दशक के उच्च स्तर 58.4 पर पहुंच गई हैं, जो महामारी के बावजूद संपर्क-आधारित सेवा क्षेत्र में एक मजबूत वृद्धि का सुझाव देती हैं। विश्राम स्थलों में औसत होटल अध्यावास दर वित्त वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में लगभग 55 प्रतिशत से बढ़कर द्वितीय में 60 प्रतिशत से अधिक होना सेवा क्षेत्र में बढ़ते आशावाद को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में खपत को मजबूत करने के लिए खुदरा ऋण उल्लेखनीय रूप से बढ़ रहा है। सीआईबीआईएल के अनुसार 2021 के फरवरी और अक्टूबर के बीच आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से इनक्वायरी वॉल्युम में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ■

15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित

यह दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सकें

गत 10 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी। यह दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सकें।

संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिज़ो जैसे कई जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया गया था। जनजातीय समुदायों के क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों को उनके अपार साहस एवं सर्वोच्च बलिदान की वजह से जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया और इसने पूरे देश में भारतीयों को प्रेरित किया।

हालांकि, देश के ज्यादातर लोग इन आदिवासी नायकों को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है। वर्ष 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के अनुरूप भारत सरकार ने देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर को श्री बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिनकी देश भर के आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूजा की जाती है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक प्रणाली के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 'उलगुलान' (क्रांति) का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।

मंत्रिमंडल की उपर्युक्त घोषणा आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकृति प्रदान करती है। यह जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा। ■

44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में दी जायेंगी 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों— आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने पांच राज्यों— आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी।

इस परियोजना के तहत आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव, जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है। इस धनराशि में पांच वर्षों का परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जायेगा। इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर यानी नवंबर 23 तक पूरा कर लिया जाना है।

जिन गांवों में ये सेवायें मौजूद नहीं हैं, उन चिह्नित गांवों में 4जी मोबाइल सेवा के प्रावधान से सम्बंधित कार्य को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किया जायेगा। यह प्रक्रिया यूएसओएफ की मौजूदा प्रणाली के तहत पूरी की जायेगी।

पांच राज्यों— आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने का मौजूदा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा, जिससे आत्मनिर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल का उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-प्रशासन संबंधी पहलें, उद्यमों और ई-वाणिज्य सुविधाओं की

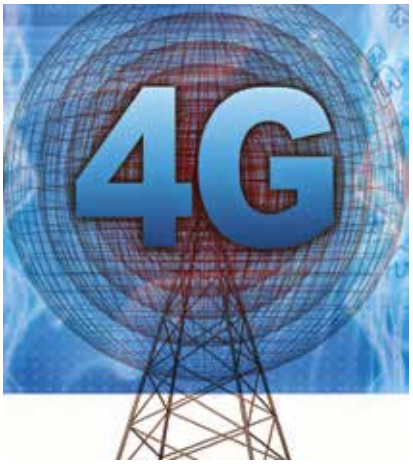

स्थापना, ज्ञान तथा रोजगार अवसरों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को पर्याप्त सहायता का प्रावधान, स्वदेशी निर्माण और 'आत्मनिर्भर भारत' आदि को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में डिजिटल इंडिया का विजन पूरा होगा। ■

फिर से खुला 'श्री करतारपुर साहिब' कॉरिडोर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 'श्री करतारपुर साहिब' कॉरिडोर का 17 नवंबर से फिर संचालन शुरू करने का निर्णय लिया। कोविड-19 महामारी के कारण 16 मार्च, 2020 से इस कॉरिडोर को निलंबित कर दिया गया था। श्री करतारपुर साहिब करोड़ों देशवासियों की असीम श्रद्धा का केंद्र है और इस कॉरिडोर का फिर से संचालन शुरू करने का निर्णय सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। मोदी सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत ने जीरो प्वाइंट, इंटरनेशनल बाउंड्री पर डेरा बाबा नानक में श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन के तौर-तरीकों पर पाकिस्तान के साथ 24 अक्तूबर, 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2018 को श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर को पूरे देश और दुनिया भर में भव्य तरीके से मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया था।

इस ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय सीमा तक डेरा बाबा नानक से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण और विकास को मंजूरी दी थी, ताकि भारत के तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा करने में सुविधा हो और यह यात्रा वर्ष भर सुचारू और सुगम तरीके से चल सके। ■

अप्रैल-अक्टूबर में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि

कृषि उत्पाद के निर्यात पर अत्यधिक जोर देते हुए भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की उसी अवधि की तुलना में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।

केंद्रीय वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के उत्पादों के कुल निर्यात में अप्रैल-अक्टूबर, 2021 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अमरीकी डॉलर के रूप में 14.7 प्रतिशत वृद्धि हुई।

एपीईडीए के उत्पादों का कुल निर्यात अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के 10,157 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर, 2021 में 11,651 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

निर्यातों में यह वृद्धि कोविड-19 के प्रतिबंधों के वाबजूद हुई है। कृषि उत्पादों के निर्यातों में इस वृद्धि को देश के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात पर जोर देते हुए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है।

मौजूदा वित्त वर्ष के प्रथम सात माह के दौरान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में यह महत्वपूर्ण वृद्धि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में निर्यात में वृद्धि की निरंतरता है। चावल के निर्यात में 10.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के 4777.35 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर, 2021 में 5278.95 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

त्वरित अनुमानों के अनुसार ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात में अमरीकी डॉलर के रूप में 11.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मोटे अनाजों से तैयार तथा विभिन्न प्रसंस्कृत सामग्रियों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-अक्टूबर, 2020-21 में ताजे फलों एवं सब्जियों का 1374.59 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया गया था, जो अप्रैल-अक्टूबर, 2021-22 में बढ़कर 1534.05 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष (2021-22) के प्रथम सात महीने में अन्य मोटे अनाज के निर्यात में 85.4 प्रतिशत की ऊंची छलांग लगाई, जबकि मांस, दूध एवं कुक्कुट उत्पादों के निर्यात में 15.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। अन्य मोटे अनाज का निर्यात अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के 274.98 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर, 2021 में 509.77 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और मांस, दूध एवं कुक्कुट उत्पादों का निर्यात अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के 1978.6 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर, 2021 में 2286.32 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

अप्रैल-अक्टूबर, 2021 में काजू के निर्यात में 29.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि अप्रैल-अक्टूबर, 2020 में काजू का निर्यात 205.29 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर, 2021 में 265.27 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। ■

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

(गतांक से...)

एक जन

भारतभूमि पर निवास करनेवाला तथा उसके प्रति ममता रखनेवाला विशाल मानव समुदाय एक जन है। अनेक विविधताओं के होते हुए भी उसमें मूलभूत एकता है। विविधताएं विकृति अथवा विघटन की सूचक नहीं, उसके स्वाभाविक विकास का परिणाम एवं सांस्कृतिक समृद्धि की परिचायक हैं। भारतीय जन की एकता की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने होंगे। परस्पर आत्मीयता और समानता के भाव जन-एकता के लिए आवश्यक है। इन भावों को विद्यालक रीतियों तथा व्यवस्थाओं को समाप्त करना होगा। ऊंच-नीच तथा छुआछूत को मिटाने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक ही नहीं अपितु सुधारवादी एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी आयोजित करने होंगे। जाति और वर्ग के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा की कल्पना और उस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक मंदिरों तथा उपासनागृहों में सबको बिना किसी भेदभाव के दर्शन का अधिकार है।

सदियों से अभिशप्त, शिक्षा तथा संस्कार की दृष्टि से पिछड़े और आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष सुविधा देनी होगी। बिना उसके उनके लिए सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की राह पर चलना संभव नहीं होगा। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछड़ेपन में लोगों का निहित स्वार्थ न बन जाए तथा जातिगत भेद मिटने के स्थान पर और रूढ़ न हो जाए।

महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयास हों, जिससे वे घर, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वाह कर सकें। जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर मिले। परदा, दहेज, बाल-विवाह, विषम-विवाह आदि कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सुधारवादी कार्यक्रम अपनाने होंगे।

मातृत्व की प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा है। मातृ-कल्याण के कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण अंग होने चाहिए। वेतन और भृति में स्त्री और पुरुष दोनों के समान स्तर रखे जाएं।

भारत के सभी जनों के विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक विधान आदि का नियमन करने के लिए एक ही व्यवहार विधि होनी चाहिए।

एक संस्कृति

एक भूमि के ऊपर एक जन के रूप में जीवित भारतीय समाज ने आसेतु हिमाचल तक जिस संस्कृति का विकास किया है, वह एक है। भारत जैसे विशाल देश में यह स्वाभाविक है कि विभिन्न प्रादेशिक, स्थानीय अथवा जातिगत जीवन पद्धतियों का विकास हो। भारतीय संस्कृति में उन सबका समन्वय हुआ है। यह कभी वाद या पंथ-विशेष से बंधी नहीं रही। परंतु वे सभी भारतीय राष्ट्र के विशाल कुटुंब के अंग रहे हैं और भारतीय संस्कृति के विकास में उन सबने भाग लिया है। इसकी धारा वैदिक काल से अब तक अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित चली आती है। समय-समय पर विभिन्न जातियों, पंथों और संस्कृतियों के संपर्क में आने पर इसने उनको इस रूप में आत्मसात् कर लिया कि वे इसके मूल प्रवाह के साथ अभिन्न हो गईं। यह भारतीय संस्कृति भारत के समान एक और अखंड है। मिली-जुली संस्कृति की चर्चा तर्क विरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत भयावह भी है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता को क्षीण कर विघटनात्मक प्रवृत्तियों को पुष्ट करती है।

भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को जनसंघ सर्वोपरि प्राथमिकता देता है। राष्ट्रीय निष्ठाओं को बलवती बनाने के भावात्मक प्रयत्नों से ही राष्ट्रीय एकता को पुष्ट किया जा सकता है

एक राष्ट्र

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति से इसके चिरकालीन इतिहास में एक नवीन अध्याय आरंभ हुआ है, किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं। स्वभावतः भारतीय राष्ट्रवाद का आधार संपूर्ण भारत एवं इसकी सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा ही हो सकता है।

भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को जनसंघ सर्वोपरि प्राथमिकता देता है। राष्ट्रीय निष्ठाओं को बलवती बनाने के भावात्मक प्रयत्नों से ही राष्ट्रीय एकता को पुष्ट किया जा सकता है तथा विघटन और विच्छेद की प्रवृत्तियों से रोका जा सकता है। प्रत्येक को उपासना पद्धति की पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए भी भारतीय जनसंघ मजहब को राजनीति के साथ मिलाने अथवा सांप्रदायिक आधार पर विशेष अधिकारों की मांग करने की प्रवृत्ति का, जो राष्ट्रीय एकात्मता में बाधक है, विरोधी है और उसे किसी

प्रकार का प्रश्रय नहीं दे सकता।

अल्पमतों के प्रति सहिष्णुता एवं पूर्ण भेदभावरहित व्यवहार राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के अनिवार्य अंग हैं। भारतीय जनसंघ सभी प्रकार के अल्पमतों को इस बात की आश्वस्ति देता है, किंतु मजहब या अन्य आधार पर भारतीय जन को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में बांटना और उसे देश की राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक नीतियों का आधार बनाना अतर्कसंगत तथा राष्ट्रीयता को शुद्ध परिकल्पना के अज्ञान का परिचायक है। राजनीतिक तथा प्रशासन में इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं पर आधारित वर्गीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है।

पाकिस्तान में रहनेवाली जनता मूलतः भारतीय राष्ट्र का अंग रही है। मुसलिम लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन तथा पाकिस्तान द्वारा इस्लामी राज्य को घोषणा से वहां के गैर-मुसलिम जन विधानतः दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। अन्याय और उत्पीड़न का शिकार बनकर वे भारत आने को विवश हुए हैं। भारतीय राज्य का यह दायित्व है कि वह इन बंधुओं को पाकिस्तान में समान अधिकार तथा सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवनयापन की सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयत्न करे अथवा उन्हें योजनापूर्वक भारत लाने, उनका पुनर्वास करने तथा क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था करे।

जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के प्रति शत्रुभावापन्न हुए एक पृथक् इस्लामी राज्य के रूप में विद्यमान है, तब तक भारत के मुसलमानों की स्थिति नाजुक है। शासन को इस बात का विशेष प्रयत्न करना होगा कि पाकिस्तानी प्रवृत्ति को जन्म देनेवाली ऐतिहासिक प्रक्रिया बदली जाए और ऐसे कोई कारण न रहें, जिससे पाकिस्तान भारत के इन नागरिकों की निष्ठा डिगाने में सफल हो सके।

भारत स्थित ईसाई एवं अन्य मतावलंबी मिशनों को विदेशी प्रभाव एवं नियंत्रण से मुक्त करना होगा, जिससे वे विदेशी शक्तियों के हाथों के खिलौने न बन सकें।

शासन व्यवस्था

एक देश, एक जन और एक संस्कृति के आधार पर एकात्मता के लिए पोषक और उसकी अभिव्यक्ति का सफल उपकरण एकात्म राज्य संविधान ही हो सकता है। संघात्मक संविधान की कल्पना राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है।

भारत की राज्य व्यवस्था तथा लोकजीवन के विकास में जनपदों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। अतः वर्तमान प्रदेशों का ऐतिहासिक एवं लोक व्यवहार के आधार पर जनपदों में परिसीमन होना चाहिए। वहां निर्वाचित जनपद सभाओं को शासन के अधिकार हों। जनपदों के अंतर्गत जिले, विकासखंड तथा पंचायतें बनाई जाएं। संपूर्ण देश के लिए विधान बनाने का अधिकार संसद को हो। जनपद सभाओं को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उपविधियों के निर्माण का तथा विधान-विशेष के लिए संसद् को संस्तुति करने का अधिकार हो। संवैधानिक राज्यपालों के स्थान पर विभिन्न जनपदों के कार्यों को समन्वित करने के लिए प्रदेशीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर प्रशासक युक्त हो।

विभिन्न निकायों के बीच शक्ति एवं साधन स्रोतों का इस प्रकार विभाजन किया जाए कि प्रत्येक आत्मनिर्भर होकर उत्तरदायी स्वायत्तता का उपभोग कर सके।

प्रशासन

प्रशासन राज्य का इतना महत्त्वपूर्ण अंग है कि सामान्य जन उसी को राज्य समझकर चलते हैं। प्रशासन का सुदक्ष, सक्षम, शुचितापूर्ण, जन-भावनाओं तथा जन-आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक जागरूक, उत्तरदायी, अनुशासित, कर्तव्यदक्ष एवं आत्मसम्मानपूर्ण होना नितांत आवश्यक है। साथ ही भृत्यवर्ग में अपनी सेवाओं और परिलाभ के संबंध में नैश्चिंत्य रहना चाहिए तथा यह विश्वास होना चाहिए कि भर्ती और पदोन्नति में पक्षपात नहीं किया जाएगा। कुशलता के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार तथा चूक के लिए दंड होना चाहिए।

सामान्यतः केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन के कर्मचारियों के वेतन और परिलाभ की दरें समान होनी चाहिए।

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही कारणों से प्रशासन में मितव्ययिता एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। सामान्य जन और प्रशासक वर्ग के जीवन स्तर में भारी अंतर असंतोष, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति तथा सामाजिक विभेद पैदा करता है। इस अंतर को कम करना होगा। प्रत्युत सभी कर्मचारियों के मन में राष्ट्र निर्माण के महान् दायित्व से सहभागी होने का भाव जाग्रत होना चाहिए तथा वही उनके कर्म की मूल प्रेरणा होनी चाहिए।

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही कारणों से प्रशासन में मितव्ययिता एक राष्ट्रीय कर्तव्य है

सरकारी कर्मचारियों के राजनीति संबंधी प्रजातंत्रीय अधिकारों को मतदान छोड़कर समाप्त करने की परंपरा चली आ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ शासकीय सेवाकर्मियों का भी विस्तार होता रहा है। समाज के इस लगातार बढ़ते हुए वर्ग को राजनीति के प्रति उदासीन बनाना प्रजातंत्र के स्वस्थ विकास की दृष्टि से अनुपयुक्त है।

अतः अधिकारी वर्ग, सामान्य प्रशासन और सेना तथा पुलिस जैसे विभागों के अतिरिक्त शेष कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए।

न्याय

न्याय सस्ता, सर्वजन सुलभ तथा अविलंबित होना चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था अंग्रेज़ी परंपरा का अनुसरण करके ही चल रही है। उसमें सुधार और परिवर्तन करना होगा।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से सब स्तरों पर पृथक् तथा मुक्त रहना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रामाणिकता में बाधक प्रवृत्तियों और व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाए। ■

क्रमशः

दार्शनिक व प्रखर राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो

(15 अगस्त, 1872 – 5 दिसम्बर, 1950)

श्री अरबिंदो का मूल नाम अरबिंदो घोष है, किंतु उन्हें अरविंद भी कहा जाता है। आधुनिक काल में भारत में अनेक महान क्रांतिकारी और योगी हुए हैं, उनमें श्री अरबिंदो अद्वितीय हैं। श्री अरबिंदो घोष दार्शनिक, कवि और प्रखर राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरबिंदो को भारतीय एवं यूरोपीय दर्शन और संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। श्री अरबिंदो का मानना है कि इस युग में भारत विश्व में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहा है तथा भविष्य में भी निभायेगा। उनके दर्शन में जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद, साहित्य और विशेषकर काव्य के क्षेत्र में उनकी कृतियां बहुचर्चित हुई हैं।

श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त, 1872 को बंगाल के कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्ण धन घोष और माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता देवी था। श्री अरबिंदो की शिक्षा दार्जिलिंग में ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में प्रारम्भ हुई और वे आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड गए। इंग्लैण्ड में श्री अरबिंदो घोष की भेंट बड़ौदा नरेश से हुई। बड़ौदा नरेश श्री अरबिंदो की योग्यता देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने श्री अरबिंदो को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया। वह बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर बने और फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल भी बने। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां पर वे तीन आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के कुशल ज्ञाता बन गए। 1892 में भारत लौटने पर उन्होंने बड़ौदा, वर्तमान वडोदरा और कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक व प्राध्यापकीय पदों पर कार्य किया।

श्री अरबिंदो के लिए 1902 से 1910 के वर्ष हलचल भरे थे, क्योंकि उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। बड़ौदा कॉलेज की नौकरी छोड़कर वह कोलकाता चले गए और कोलकाता के 'नेशनल कॉलेज' के प्रिंसिपल बने। इस समय तक उन्होंने 'सादा जीवन और उच्च विचार' जीवन अपना लिया। उन पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के साहित्य का गहन प्रभाव था।

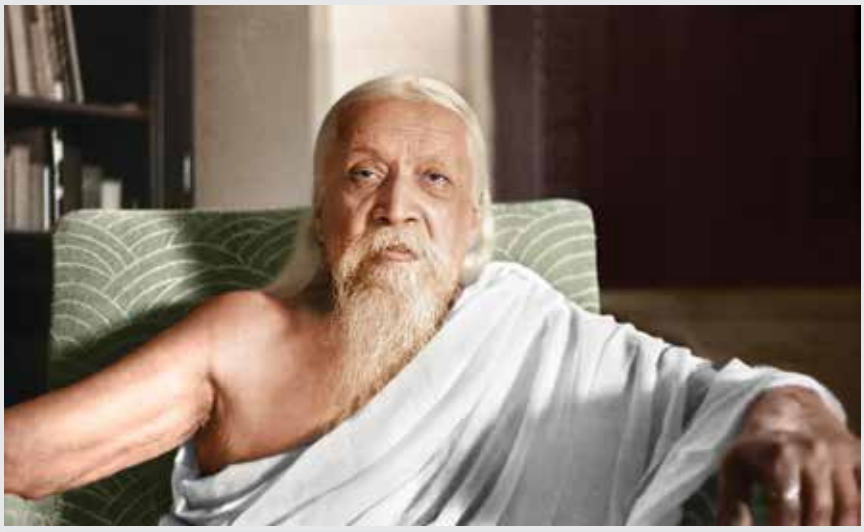

सन् 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, ताकि हिन्दू और मुसलमानों में फूट पड़ सके। इस बंग-भंग के कारण बंगाल में जन-जन में असंतोष फैल गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्री अरबिंदो घोष ने इस जन आंदोलन का नेतृत्व किया

सन् 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, ताकि हिन्दू और मुसलमानों में फूट पड़ सके। इस बंग-भंग के कारण बंगाल में जन-जन में असंतोष फैल गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्री अरबिंदो घोष ने इस जन आंदोलन का नेतृत्व किया। वे 1906 से 1909 तक सिर्फ तीन वर्ष के लिए प्रत्यक्ष राजनीति में रहे। इतने अल्प समय में भी वे लोगों के अति प्रिय बन गए। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस लिखते है— जब मैं 1913 में कलकत्ता आया, अरबिंदो तब तक किंवदंती बन चुके थे। जिस आनंद तथा उत्साह के साथ लोग उनकी चर्चा करते शायद ही किसी की वैसी करते। दो वर्ष बाद ब्रिटिश भारत को छोड़कर श्री अरबिंदो दक्षिण भारत स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन पूर्णरूपेण अपना दर्शन विकसित करने में लगा दिया।

पांडिचेरी आने के बाद वे सांसारिक कार्यों से अलग होकर आत्मा की खोज में लग गए। वहां पर श्री अरबिंदो अंत तक योगाभ्यास करते रहे और उन्हें परमात्मा से साक्षात्कार की अनुभूति हुई। उनका दृढ़ विश्वास था कि संसार के दुःख का निवारण आत्मा के विकास से हो सकता है, जिसकी प्राप्ति केवल योग द्वारा ही संभव है। वे मानते थे कि योग से ही नई चेतना आ सकती है। श्री अरबिंदो का देहांत 5 दिसम्बर, 1950 को पांडिचेरी में हुआ। ■

गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 'आईएनएस विशाखापत्तनम' राष्ट्र को समर्पित

गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 'आईएनएस विशाखापत्तनम' को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 21 नवंबर, 2021 को नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने आईएनएस विशाखापत्तनम को देश की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में एक मील का पत्थर बताया।

श्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि नवीनतम प्रणालियों और हथियारों से लैस यह अत्याधुनिक जहाज समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और राष्ट्र के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने इस जहाज को दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में परिभाषित किया, जो सशस्त्र बलों और पूरे राष्ट्र की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

उल्लेखनीय है कि आईएनएस विशाखापत्तनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर है और विस्थापन की इसकी क्षमता 7,400 टन है और यह भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। जहाज को चार शक्तिशाली गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाता है, जो 30 समुद्री मील से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है। जहाज अत्याधुनिक हथियारों और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे सेंसर से लैस है। ■

आईएनएस विशाखापत्तनम का लोकार्पण एक गौरवशाली दिवस: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 नवंबर को स्वदेशी स्तर पर डिजाइन किये गये आईएनएस विशाखापत्तनम के लोकार्पण को गौरवशाली दिवस कहा। श्री मोदी ने यह भी दोहराया कि रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के प्रयास पूरे दम-खम के साथ जारी रहेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा का गौरवशाली दिवस है। आईएनएस विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में कमीशन दे दिया गया है। इसे स्वदेशी स्तर पर ही विकसित किया गया है और इससे हमारे सुरक्षा-तंत्र को मजबूती मिलेगी। रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में हमारे प्रयास पूरे दम-खम के साथ जारी रहेंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और चार महीने तक विस्तार देने को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री द्वारा सात जून, 2021 को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में लोकहित में की गई घोषणा तथा कोविड-19 के संदर्भ में आर्थिक पहलों के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण पांच) को और चार महीने यानी दिसंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त घरों) के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा।

इस योजना का पहला और दूसरा चरण क्रमशः अप्रैल से जून, 2020 और जुलाई से नवंबर, 2020 में परिचालन में था। योजना का तीसरा चरण मई से जून, 2021 तक परिचालन में रहा। योजना का चौथा चरण इस समय जुलाई-नवंबर, 2021 के दौरान चल रहा है।

पीएजीकेएवाई योजना का पांचवां चरण दिसंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक चलेगा, जिसमें अनुमानित रूप से 53344.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी दी जायेगी। पीएमजीकेएवाई के पांचवें चरण के लिये खाद्यान्न का कुल उठान लगभग 163 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है।

यह याद रहे कि पिछले वर्ष देश में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आने वाली आर्थिक अड़चनों को मद्देनजर रखते हुये केंद्र सरकार ने मार्च, 2020 में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति माह के हिसाब से पांच किलोग्राम अतिरिक्त रूप से निःशुल्क अनाज (चावल/गेहूं) दिया जायेगा।

अब तक पीएम-जीकेएवाई (एक से चार चरण तक) के तहत विभाग ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 600 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया है, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।

पीएमजीकेएवाई-चौथे चरण के अंतर्गत वितरण इस समय चल रहा है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 93.8 प्रतिशत अनाज उठा लिया गया है और लगभग 37.32 एलएमटी (जुलाई, 2021 का 93.9 प्रतिशत), 37.20 एलएमटी (अगस्त, 2021 का 93.6 प्रतिशत), 36.87 एलएमटी (सितंबर, 2021 का 92.8 प्रतिशत), 35.4 एलएमटी (अक्टूबर, 2021 का 89 प्रतिशत) और 17.9 एलएमटी (नवंबर, 2021 का 45 प्रतिशत) अनाज क्रमशः लगभग 74.64 करोड़, 74.4 करोड़, 73.75 करोड़, 70.8 करोड़ और 35.8 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया। ■

प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी की पहली किस्त हस्तांतरित की

आज देश के विकास को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना से देखा जाता है। विकास को अब देश की एकता-अखंडता का पर्याय माना जाता है

गत 14 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी की पहली किस्त हस्तांतरित की। इस अवसर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए। प्रधानमंत्री की पहल के बाद त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से राज्य के लिए 'कच्चा' घर की परिभाषा बदल दी गई है। परिणामस्वरूप, इतनी बड़ी संख्या में 'कच्चे' घरों में रहने वाले लाभार्थी 'पक्का' घर बनाने के लिए सहायता प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत भी की।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम त्रिपुरा के लिए आने वाले अच्छे दिनों तथा उम्मीद का संकेत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में बिप्लब देब जी की सरकार और केन्द्र की सरकार राज्य की प्रगति को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब-करीब डेढ़ लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरावासियों को हृदय से बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख-सुविधाओं से दूर रखने वाली सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत और ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है।

क्षेत्र के प्रति लंबे समय से व्याप्त उपेक्षा की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब की ओर आती थीं, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए, हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन आज देश के विकास को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना से देखा जाता है। विकास को अब देश की एकता-अखंडता का पर्याय माना जाता है।

श्री मोदी ने देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत की आत्मविश्वास से भरपूर महिला शक्ति की विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक, हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं। इन एसएचजी को जन-धन खातों के साथ जोड़ा गया है। ऐसे समूहों के लिए उपलब्ध बिना गिरवी के ऋण को दोगुना कर बीस लाख रुपये कर दिया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर और देश के आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक और बड़ा फैसला किया है। देश अब हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाएगा। 2 अक्टूबर-अहिंसा दिवस, 31 अक्टूबर-एकता दिवस, 26 जनवरी-गणतंत्र दिवस, राम नवमी, कृष्ण अष्टमी आदि के रूप में इस दिन को राष्ट्रीय आइकनोग्राफी में समान महत्व मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस न केवल जनजातीय समाज के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन होगा, बल्कि यह सौहार्दपूर्ण समाज के प्रतीक के रूप में भी उभरेगा। ■

जन-मन को भाती— मन की बात

शिवप्रकाश
राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री
भाजपा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के विकास एवं गरीब उत्थान के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। देश की जनता ने जिस प्रकार उत्साह के साथ वोट दिया था, उनसे वैसी ही अपेक्षा थी। राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी नेता राजनीतिक विषयों पर सदैव टिप्पणी करते ही हैं। नेताओं की टिप्पणी अपने दल उसकी नीतियों के समर्थन एवं विरोधी दलों के विरोध में ही होती है। वोट इस प्रकार के वक्तव्यों का आधार होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सबसे हटकर एक नई पहल प्रारंभ की, जो उनकी समाज के प्रति संवेदनशीलता, देश की जनता के मानस की सूक्ष्म अध्ययन दृष्टि एवं सामाजिक विषयों के प्रति समाज से अपेक्षित सक्रियता को प्राप्त करना, इस उद्देश्य को प्रकट करती है। इस पहल को देश 'मन की बात' के नाम से जानता है। आकाशवाणी पर प्रतिमाह के अंतिम रविवार को आने वाली मन की बात अब देश एवं दुनिया में लोकप्रिय है। इसकी जनप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 27 जनवरी 2015 को मोदीजी के साथ मन की बात में सहभागिता कर चुके है। सतत आने वाली मन की बात की हम 82 वी श्रृंखला सुन चुके है। लाखों स्थानों पर करोड़ों लोग अपनी-अपनी भाषाओं में एकत्रित होकर मन की बात सुनते हैं। मृतप्राय हो चुकी रेडियो व्यवस्था एवं अप्रासंगिक जैसे लगने वाली आकाशवाणी को मन की बात ने पुनः प्रासंगिक बना दिया है। बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी, आलोचना, प्रत्यालोचना के मन की बात ने देश भर में सकारात्मक वातावरण निर्माण किया है। समाज के सम्मुख ज्वलंत समस्याओं का निदान, रचनाधर्मी पुरुषों एवं प्रकल्पों को आगे बढ़ाया है। समस्याओं से लड़ने वाला समाज भी सक्रिय किया है। समाज की सक्रियता ही जागृत लोकतंत्र की पहचान है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदीजी के बहुआयामी व्यक्तित्व का दर्शन भी कराया है। जिससे देश में उनके प्रति विश्वास बहुगुणित हो गया है।

अभी देश के लगभग 1.5 लाख स्थानों पर इसको सुना जाता है। देश के सभी ग्रामों- शहरों के मोहल्लों में मन की बात सुने यह प्रधानमंत्रीजी की अपेक्षा है। देश भर में सामूहिक एवं परिवार सहित सुने, सुनने के बाद चर्चा करें एवं प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में इस प्रकार के उपक्रम चलाएं। इस सामूहिक शक्ति से जो ताकत निर्माण होगी वह विश्व में भारत माता के जयघोष कराने में सहयोग करेगी। इसी में इस अभिनव प्रयोग 'मन की बात' की सार्थकता है

जब हम अपने देश की तुलना विकसित देशों के साथ करते हैं तब एक सहज टिप्पणी आती है कि वहां के नागरिकों के दैनंदिन जीवन में व्यवहार का विवेक एवं अनुशासन है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी अपने अनुभवों का इस संबंध में उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने अपने देश के नागरिकों के व्यवहार में यह अनुशासन आए, स्वच्छता अभियान के माध्यम से इसका प्रयास किया, इसका आधार बनी 'मन की बात'। दैनंदिन जीवन में सफाई से प्रारंभ करके आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शी व्यवहार, कालाधन आदि समस्याओं को मन की बात के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया। समाज में दुर्व्यसन रोकने का माध्यम भी मन की बात बनी।

समाज के सम्मुख प्रदूषण का संकट है। पर्यावरण बचाने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु जल की शुद्धता, वृक्षारोपण जैसे विषयों को प्रधानमंत्री मोदीजी ने मन की बात में उठाया। 24 अक्टूबर 2021 मन की बात में गाजियाबाद के पॉन्ड मैन श्री रामवीर तंवर जी का उल्लेख कर जल के महत्व को मोदीजी ने समझाया। मोदीजी द्वारा उल्लेखित जल का हमारे जीवन में कितना महत्त्व है इसको निम्न श्लोक से समझा जा सकता है।

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मदा सिन्धु कावेरी जले अस्मिन्
सन्निधम कुरु।।

खादी पुनः आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनी। खादी खरीदने का आह्वान श्री नरेन्द्र मोदीजी ने मन की बात के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि "आइए हम खादी उत्पाद खरीदें और बापू की जयंती को बड़े उत्साह के साथ चिह्नित करें" एवं "खादी को कपड़े की तरह नहीं आन्दोलन की तरह देखें।" जिसका परिणाम हुआ खादी पुनः जन चेतना जागृति का माध्यम बनी। किसान की समस्याओं को उठाना, कृषि एवं किसानों का उचित मार्गदर्शन करना, कृषि के क्षेत्र में चलने वाले अच्छे प्रयोगों को आगे लाना सभी मन की बात के माध्यम से हुआ। ड्रोन पोलिसी से कृषि का लाभ बढेगा, इस कारण ड्रोन पोलिसी समझाने का माध्यम भी मन की

बात बनी।

21 जून योग दिवस अब विश्व भर में विशेष दिवस हो गया। दुनिया के समस्त देशों में योग के बड़े-बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जल, थल, नभ सभी में योग के कार्यक्रम होते हैं। भारत में तो सभी शिक्षण संस्थानों सहित गांव-गांव योग होता है। योग गुरु एवं सामाजिक संस्थाएं योग के विस्तार में सहायक हो रही हैं। योग को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मन की बात का बहुत बड़ा योगदान है। मोदीजी ने मन की बात में कहां कि "योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी, सबके लिए अच्छा है।" बच्चों के विकास में खिलौनों का महत्त्व समझाते हुए मोदीजी कहते है कि गुरुवर रवीन्द्र नाथ ठाकुर कहते थे कि "सबसे अच्छा खिलौना वो है जो अधूरा हो और जिसको बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से पूरा करें।"

परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों पर परीक्षा का एक दबाव रहता है। इस दबाव का परिणाम होता है कि असफलता के भय से अनेक छात्र आत्महत्या करते हैं। प्रसन्न मन से तैयारी कैसे करें, परीक्षा के दिनों में अभिभावकों का कैसा व्यवहार हो यह समझाने में मोदीजी ने सफलता प्राप्त की है। "हमारी प्रतियोगिता दूसरों से नहीं स्वयं से ही है।" मन की बात में उल्लेखित यह उनका प्रसिद्ध वाक्य है। अब तो मन की बात के लिए देश के हजारों लोग अपने सुझाव भी देते हैं।

कोरोना महामारी को रोकने में भारत ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। भारत का टीकाकरण अभियान भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभियान बना है। कोरोना के समय समाज का व्यवहार, कोरोना योद्धाओ को सम्मान, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन, कोरोना के विरुद्ध समाज को खड़ा करना, इन सभी विषयों को जनता तक ले जाने में मन की बात कार्यक्रम सहायक बना है। कोरोना महामारी से उसकी समाप्ति तक सजग रहने का आह्वान करते हुए मोदी जी निम्न श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि –

अग्निः शेषं ऋणः शेषं शत्रुः शेषं तथैव च ।
पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषं न कारयेत् ।।

देशभर में नकारात्मक घटनाओं की चर्चा बहुत होती है। लेकिन समाज को खड़ा करने के लिए नकारात्मकता नहीं सकारात्मक वातावरण चाहिए। रचनाधर्मिता से युक्त प्रयोग समाज के सामने जितने आएंगे उससे समाज का विश्वास बढ़ेगा। इसलिए अच्छी सूचनाएं अच्छे विचार एवं अच्छे कार्य को आगे लाना होता है। किसी कवि ने कहा कि "अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि एक दीप जलाएं।" इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्रीजी द्वारा देश भर में चलने वाले अच्छे प्रयोग, अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। प्रतिमाह की मन की बात इन अनेक प्रसंगों से भरी पड़ी है जो हमको भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

'मन की बात' में प्रधानमंत्रीजी आगामी माह में आने वाले उत्सवों का महत्व एवं शुभकामनाएं देते हैं। महापुरुषों के जन्मदिन की चर्चा करते हुए बधाई देते हैं एवं उस महापुरुष का देश एवं समाज के प्रति योगदान क्या है इसकी चर्चा करते हैं। इस कारण महापुरुष एवं उत्सव-त्योहार किसी एक वर्ग के नहीं संपूर्ण समाज के हैं यह दृष्टि बोध होता है। महापुरुषों की चर्चा करते समय उनके कहे वाक्य, रचित काव्य की कुछ पंक्तियां एवं संस्कृत श्लोक, अंग्रेजी उक्ति सभी का उल्लेख करते हैं। जिसके कारण सभी भाषाओं के महापुरुषों, उत्सवों के प्रति श्रद्धा एवं सभी हमारे हैं, यह एकात्मता का भाव जगता है। यह एकात्मता ही देश को एक रखने में सहायक है। मन की बात में बिरसा मुंडा एवं सरदार पटेल के वाक्यों का उल्लेख इसके महत्त्व को दर्शाता है ।

गरीब कल्याण, महिलाओं का सम्मान, दिव्यांगों को सहयोग, सरकार के कार्यक्रमों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी एवं जनता से अपेक्षा, समाज के प्रति संवेदना, भविष्य की चुनौतियों से लड़ने योग्य समाज का दिशा-दर्शन, नए-नए प्रयोग खड़े करते हुए व्यवहारिक देशभक्ति युवा प्रकट करें, संस्कृति के प्रति गौरव जैसे गुणों को विकसित करने का माध्यम मन की बात बनी है। अभी देश के लगभग 1.5 लाख स्थानों पर इसको सुना जाता है। देश के सभी ग्रामों- शहरों के मोहल्लों में मन की बात सुने यह प्रधानमंत्रीजी की अपेक्षा है। देश भर में सामूहिक एवं परिवार सहित सुने, सुनने के बाद चर्चा करें एवं प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में इस प्रकार के उपक्रम चलाएं। इस सामूहिक शक्ति से जो ताकत निर्माण होगी वह विश्व में भारत माता के जयघोष कराने में सहयोग करेगी। इसी में इस अभिनव प्रयोग 'मन की बात' की सार्थकता है। ■

उत्तर प्रदेश के महोबा में विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित

किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है: नरेन्द्र मोदी

पहली बार बुंदेलखंड के लोग, यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार को देख रहे हैं। पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश को लूटते नहीं थकती थीं, हम काम करते-करते नहीं थकते हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा में विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को वो राहत मिलेगी, जिसकी जरूरत उन्हें बहुत पहले से थी। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भाओनी बांध परियोजना और मझगांव-चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना शामिल हैं।

इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपये से अधिक है और इनके संचालन से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र को पेयजल भी प्राप्त होगा। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा राज्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे।

श्री मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने-कोने में ले आए हैं, महोबा उसका साक्षात गवाह है। उन्होंने कहा कि ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है, जिन्होंने देश की गरीब माताओं-बहनों-बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं।

श्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को 'तीन तलाक' के अभिशाप से मुक्त कराने के अपने वादे को स्मरण किया जो उन्होंने महोबा की धरती से किया था, आज वादा पूरा हुआ। 'उज्ज्वला 2.0' को भी यहीं से लॉन्च किया गया था।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने बुंदेलखंड को लूटकर अपने परिवारों का भला किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें आपके परिवारों की पानी की समस्या के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने दशकों तक ऐसी सरकारों को देखा है जिन्होंने उन्हें लंबे समय तक लूटा है। उन्होंने कहा कि पहली बार बुंदेलखंड के लोग, यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार को देख रहे हैं। पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश को लूटते हुए नहीं थकती थीं, हम काम करते-करते नहीं थकते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं। केन-बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने सभी पक्षों के साथ संवाद करके निकाला है।

उन्होंने कहा कि परिवारवादियों की सरकारें किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थीं। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। जबकि हमने पीएम किसान सम्मान निधि से अब तक 1,62,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि हम बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और यूपी डिफेंस कॉरिडोर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ■

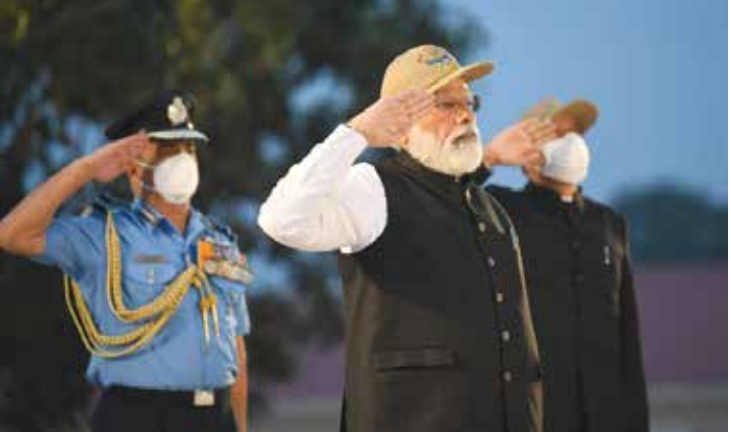

आज देश का मंत्र है– 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड': नरेन्द्र मोदी

गत 19 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व' में भाग लिया। श्री मोदी ने झांसी किले के प्रांगण में आयोजित 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व' के एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई नई पहलों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ भी शामिल है। प्रधानमंत्री को इस संघ के प्रथम सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया। एनसीसी कैडेटों के लिए राष्ट्रीय सिमुलेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ; राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कियोस्क; राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का मोबाइल ऐप; भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन एवं विकसित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट 'शक्ति'; हल्का लड़ाकू हेलीकाप्टर और ड्रोन भी इन परियोजनाओं में शामिल है।

श्री मोदी ने झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रामेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला भी रखी। इस ऊर्जा पार्क का निर्माण 3000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जा रहा है और यह सस्ती बिजली एवं ग्रिड स्थिरता के दोहरे लाभ प्रदान करने में मदद करेगा। उन्होंने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने वीरता और पराक्रम की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती का उल्लेख किया और कहा कि आज झांसी की यह धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है।

उन्होंने कहा कि उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली यानी काशी का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, कार्तिक पूर्णिमा और देव-दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। श्री मोदी ने वीरता और बलिदान के इतिहास में योगदान के लिए कई नायकों और नायिकाओं को श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने कहा कि यह धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रहीं वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की उस अमर वीरांगना के चरणों में भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं इस धरती से भारतीय शौर्य और संस्कृति की अमर गाथाएं लिखने वाले चंदेलों-बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की वीरता का लोहा मनवाया। मैं नमन करता हूं बुंदेलखण्ड के गौरव, उन वीर आल्हा-ऊदल को, जो आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज एक ओर हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की शुरुआत की है। 33 सैनिक स्कूलों में इस सत्र से गर्ल्स स्टूडेंट्स के एडमिशन शुरू भी हो गए हैं। सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेंगी जो देश की रक्षा-सुरक्षा, विकास की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगी। एनसीसी पूर्व छात्र संघ के पहले सदस्य के रूप में पंजीकृत प्रधानमंत्री ने साथी पूर्व छात्रों से राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आने और हर संभव तरीके से योगदान देने का आह्वान किया।

सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेंगी जो देश की रक्षा-सुरक्षा, विकास की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगी

श्री मोदी ने कहा कि मेरे पीछे ये ऐतिहासिक झांसी का किला, इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते, तो देश की आज़ादी का इतिहास शायद कुछ और होता।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है, लेकिन आज देश का मंत्र है- 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड'। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि झांसी इस उद्यम का प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरेगा।

श्री मोदी ने कहा कि 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व' जैसे आयोजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का वातावरण तैयार करने में बेहद मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय नायकों और नायिकाओं का इसी तरह भव्य तरीके से गुणगान करने की जरूरत है। ■

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधनः विश्व को भारत का उपहार

राम प्रसाद त्रिपाठी

इसी साल नवंबर 2021 में कॉप-26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य देश के तौर पर शामिल हो गया, जलवायु मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री जॉन केरी ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है।

इसी ग्लासगो शिखर सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) ने भी वैश्विक प्रयासों के अनुरूप महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन में देशों को सहयोग और समर्थन करने के लिए सहमति के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों वैश्विक संस्थान अब संयुक्त रूप से ऊर्जा क्षेत्र में अल्पीकरण की कार्रवाई के कार्यान्वयन को सामूहिक रूप अंजाम देने का प्रयास करने साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीतियों के कार्यान्वयन पर भी काम करेंगे। यह समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छोटे राष्ट्रों और कम विकसित देशों सहित विकासशील देशों को डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों के लिए नीति विकल्पों और दृष्टिकोणों को अपनाने में तेजी लाने में सहायता प्रदान करेगा।

इसी तरह कॉप-26 ग्लासगो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति से पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक ठोस शुरुआत है। भारत के संकल्प को अपनाने से निश्चित रूप से हरित ऊर्जा कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत होगी।

ये हालिया घटनाक्रम न केवल आईएसए को एक वैश्विक संस्था के रूप में स्थापित करेंगे, जो सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर, सौर ऊर्जा अपनाते हुए उत्सर्जन में कमी लाने के ध्यये पर काम करता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेंगे । निस्संदेह, आईएसए के साथ ये सहयोग और हाल ही में इज़राइल, ग्रीस, संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 से अधिक सदस्य देशों की उपस्थिति निश्चित रूप से स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु चुनौतियों के लिए दीर्घकालिक, लागत प्रभावी और प्रभावशाली समाधान सामने लाने में मदद करेगा।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), जिसे नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) के 21वें सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति श्री फ्रेंकोइस ओलांद द्वारा शुरू किया गया था, वह सौर ऊर्जा के लिए वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने में मदद करके सौर ऊर्जा विकास को उत्प्रेरित करने के लिए वैश्विक जनादेश के साथ एक अंतर-सरकारी संधि-आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा को एक साझा समाधान के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो एक साथ भौगोलिक स्तर पर जलवायु, ऊर्जा और आर्थिक प्राथमिकताओं को संबोधित करता है, राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा, और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करता है। आईएसए बड़े देशों की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है, साथ ही आर्थिक रूप से अधिक कमजोर देशों को एक आत्मनिर्भर ऊर्जा विकल्प स्थापित करने में मदद मिलती है जो व्यापार निर्भरता को कम करता है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।

यह गठबंधन सौर ऊर्जा को एक साझा समाधान के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो एक साथ भौगोलिक स्तर पर जलवायु, ऊर्जा और आर्थिक प्राथमिकताओं को संबोधित करता है

ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए विभिन्न मंचों पर विभिन्न देश अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे है, इसको लेकर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया की अपेक्षा से अधिक काम कर रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भी है, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में यह भारत का "दुनिया को सच्चा उपहार" है।

भारत, जो लाखों लोगों के लिए जीवन की सुगमता में सुधार के लिए अथक प्रयास कर रहा है, और दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत होने के बावजूद 5 प्रतिशत वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उसने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वह अपने दायित्वों को दृढ़ता से पूरा करे। आज पूरी दुनिया यह मानती है कि भारत ही एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस की प्रतिबद्धता को अक्षरशः पूरा किया है।

निस्संदेह भारत अक्षय ऊर्जा को आक्रामक रूप से बढ़ावा देकर, पृथ्वी को बचाने के लिए 'और अधिक' प्रयास कर रहा है। पांच साल पहले, भारत में केवल 3 गीगावॉट सौर ऊर्जा पैदा हो रही थी; प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा

शेष पृष्ठ ३१ पर...

गति शक्ति विभागों के आपसी दूरी को कम करके उनके बीच समन्वय स्थापित करेगी

विकास आनन्द

गतिशक्ति क्या है?

देश में बुनियादी ढांचे की तेजी से विकास के लिए गति शक्ति योजना की शुरुआत की गयी है। खासकर आधारभूत ढांचे से सम्बंधित विभागों में समन्वय नहीं होने के वजह से पूरे देश को सड़क, रेल, समुद्री मार्ग और हवाई मार्ग से जोड़ने अर्थात् 'मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी' के कार्य में अनावश्यक देरी हो रही थी। अतः देश के बहुयामी विकास में तेजी लाने के लिए 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गति-शक्ति योजना का प्रारंभ किया गया। आधारभूत संरचना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। यह मंच एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ समन्वयित करेगा। यह भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाहों, उड़ान आदि सम्बंधित विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं में इसके द्वारा समन्वय स्थापित किया जाएगा।

गति शक्ति क्यों?

बुनियादी ढांचा विकास की कुंजी है। इस लिए इन योजनाओं का तेजी से कार्यान्यवन सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते हैं कि यह अनिवार्य है कि भारत में शासन अधिक कुशल और उत्तरदायी हो। उनके द्वारा 'प्रगति'(PRAGATI) मंच का शुभारंभ इसी दिशा में एक कदम था। भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने महत्वाकांक्षी बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की शुरुआत की। इस प्लेटफार्म द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करते हैं। यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव आते हैं। यह भी परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाता है। लेकिन यह पाया गया कि आधारभूत संरचना से सम्बंधित विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी है और विकास प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी हो रही है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार, यातायात के हिस्से पर सड़कें हावी हैं। भारत में 64% माल ढुलाई सड़कों के माध्यम से की जाती है। चूंकि डीजल, सड़क परिवहन को संचालित करता है, तेल की कीमतों में कोई भी वृद्धि, उच्च परिवहन लागत का कारण बनती हैं और कीमतें बढ़ाती है । यहां तक कि जीएसटी, फास्टटैग और अन्य पहलों के बाद भी परिवहन हिस्सेदारी में रेलवे के एक उच्च हिस्से की आशा करना वांछनीय है क्योंकि यह एक अधिक कुशल तरीका और तुलनात्मक सस्ता है। इसके अलावा कई आर्थिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों, लॉजिस्टिक केंद्रों और बंदरगाहों की योजना 'बहु-मॉडल कनेक्टिविटी' के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। निर्णय लेने की खंडित प्रकृति, विभागों के काम करने में आपसी दूरी, एक असंबद्ध औद्योगिक नेटवर्क इनके समस्याओं की जड़ है। एक अक्षम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती है।

गतिशक्ति विभागों के बीच समन्वय की कमी को कैसे दूर करेगा?

अमिताभ कांत कहते हैं, एक कुशल, निर्बाध मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक व्यापक मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित, प्रभावकारी समन्वय और सहयोग में काम करने के लिए स्वतंत्र सरकारी विभागों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने 2021 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय मास्टर प्लान, गतिशक्ति हमारे करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने में मदद करेगी। गतिशक्ति कार्यक्रम विभागों के बीच की दूरी को तोड़ने के लिए निर्णय लेने में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। प्रस्तावित योजना में, सभी मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को एक ही प्लेटफॉर्म में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैप किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों की अलग-अलग परियोजनाओं की जांच की जाएगी और भविष्य में समग्र योजना के मापदंडों के भीतर मंजूरी दी जाएगी, जिससे प्रयासों में तालमेल बिठाया जा सकेगा। गतिशक्ति भारत में एक विश्वस्तरीय, निर्बाध मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क बनाने के लिए तालमेल लाएगी। राष्ट्रीय मास्टर प्लान बुनियादी ढांचे की समन्वित योजना के लिए आधुनिक तकनीक और नवीनतम आईटी उपकरणों को नियोजित करेगा। निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया जाएगा। समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने और संभावित मुद्दों को चिह्नित करने और परियोजना की निगरानी में डिजिटलीकरण एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

शेष पृष्ठ 31 पर...

'पीपल्स पद्म' पुरस्कार: गौरव को पुनर्स्थापित किया

विपुल शर्मा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही पद्म पुरस्कारों के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिये थे और प्रधानमंत्री श्री मोदी के ईमानदार प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं, ऐसा ही कुछ हमें 8 नवंबर को देखने को मिला जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 और 2021 के विजेताओं को नई दिल्ली में इन प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं की सूची ने सुर्खियां बटोरीं और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इन पुरस्कारों पर अब किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं है। पुरस्कार विजेता उन लोगों में से थे जो बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसमें नंगे पांव पुरस्कार लेने पहुंची कर्नाटक की पर्यावरणविद् तुलसी गौड़ा भी शामिल थीं और नारंगी बेचने वाले और स्कूल बनाने वाले हरेकाला हजब्बा भी शामिल थे, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि इन पुरस्कार के माध्यम से अब उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो वास्तव में इसके हकदार हैं और जो राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री – भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, जो सामाजिक कार्य, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, खेल और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में शुरू किए गए थे और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, श्री अरुण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज, जार्ज फर्नांडिस और रामविलास पासवान जैसी हस्तियों को दिए जा चुके हैं।

पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने और इस पूरी प्रक्रिया में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में एक वेबसाइट लॉन्च

की थी। चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया और पद्म पुरस्कार समिति का विस्तार किया गया। इससे चयन प्रक्रिया में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया है और उसी वर्ष बहुत ही विनम्र और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विजेताओं की सूची में मीनाक्षी

पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने और इस पूरी प्रक्रिया में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में एक वेबसाइट लॉन्च की थी। चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया

अम्मा शामिल थीं, जो लगभग 70 वर्षों से कलारीपयट्टू का अभ्यास और शिक्षण दे रही थीं, जिनको लोकप्रिय तौर पर 'तलवार वाली दादी' के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सक्रियता को संरक्षित करने के लिए लोक गायिका सुकरी बोम्मगौड़ा को भी इस साल सम्मानित किया गया।

इन वर्षों के दौरान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार को 2020 पुरस्कारों के लिए 46,000 नामांकन प्राप्त हुए, वहीं 2014 में केवल 2,200 नामांकन आए थे। सरकार ने 2018 में पद्म प्रतियोगिता भी शुरू की, यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी, जो विजेताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है।

योग्य लोगों को नामांकित करने से लेकर पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करने का मौका मिलने तक, सरकार ने इन पुरस्कारों की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया है। इन पुरस्कारों को अब 'पीपल्स पद्म' के रूप में संदर्भित किया जा रहा है क्योंकि वे भारत की 1.4 बिलियन आबादी का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं, न कि केवल विशिष्ट वर्ग का।

तुलसी गौड़ा– कर्नाटक के अंकोला तालुक के होन्नाली गांव की रहने वाली तुलसी गौड़ा एक पर्यावरणविद् हैं, जिन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। वह पिछले छह दशकों से पर्यावरण संरक्षण और संबंधित गतिविधियों में शामिल रही हैं। उन्हें अक्सर 'जंगल का विश्वकोष' कहा जाता है और उसकी जनजाति के लोग उनको जंगल के पेड़ और पौधों की व्यापक जानकारी के लिए 'पेड़ देवी' भी कहते है।

हरेकाला हजब्बा– कर्नाटक के

मंगलुरु के नारंगी विक्रेता हरेकाला हजब्बा ने अपनी कमाई के पैसों से अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। जो अब सरकार और निजी संस्थाओं के समर्थन से विकसित किया गया है और इसे हजब्बा स्कूल के रूप में जाना जाता है।

कृष्णम्मल जगन्नाथन– तमिलनाडु राज्य से आने वाली कृष्णम्मल जगन्नाथन, जिन्हें प्यार से 'अम्मा' के नाम से जाना जाता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अहिंसा के सिद्धांत के प्रचार के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करती रही हैं। 1926 में जन्मी जगन्नाथन ने भूमिहीनों और गरीबों के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है।

राहीबाई सोमा पोपेरे– 'बीज मां' के रूप में लोकप्रिय, रहीबाई सोमा पोपरे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कोम्बले गांव की एक महादेव कोली आदिवासी किसान हैं। वह गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पायी, इसलिए उन्होंने दस साल की उम्र में अपने परिवार की मदद करने के लिए कृषि और गाय पालन का काम शुरू किया। स्कूल न जाने के बावजूद उन्होंने अपने अभ्यास और अनुभव से कृषि जैव विविधता, जंगली खाद्य संसाधनों और पारंपरिक संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरस्कार विजेताओं की सराहना करते हुए कहा, पर्यावरण से उद्यम तक, कृषि से कला तक, विज्ञान से समाज सेवा तक, लोक प्रशासन से सिनेमा तक ... पीपल्स पद्म के प्राप्तकर्ता विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं आप सभी से प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का आग्रह करता हूं, जिससे सभी प्रेरित हों।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई देते हुए कहा, मोदी सरकार ने योग्य लोगों को पद्म पुरस्कार देकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी को दिल से बधाई देता हूं और पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी को बधाई देता हूं। देश को आप सभी पर गर्व है। ■

पृष्ठ १४ का शेष...

क्षमता के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें 100 गीगावाट ऊर्जा सौर शामिल है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

हर साल दुनिया की आबादी से ज्यादा यात्री भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे प्रणाली ने 2030 तक खुद को 'नेट जीरो' बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले इस पहल से उत्सर्जन में सालाना 60 मिलियन टन की कमी आएगी। इसी तरह, बड़े पैमाने पर एलईडी बल्ब अभियान उत्सर्जन में सालाना 40 मिलियन टन की कमी कर रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ ऐसी कई पहलों पर तेज गति से काम कर रहा है।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के तौर पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की क्योंकि कई विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व पर भारी पड़ रहा था। यह लाखों लोगों की जान बचाने के लिए भारत की एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। यह समय की मांग है और आईएसए इसकी प्रासंगिकता साबित कर रहा है। जैसा कि अपेक्षित था, आईएसए भारत को जलवायु के विषय पर बड़े साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। यह निश्चित रूप से पृथ्वी के लिए स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। ■

पृष्ठ ११ का शेष...

यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में कैसे सहायक होगा?

मिंट के विश्लेषण के अनुसार, भारत की लॉजिस्टिक्स लागत बहुत अधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 13%है। यह भारत में अधिकांश उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बनाता है। सुगम परिवहन से कम लॉजिस्टिक्स लागत निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। कमजोर परिवहन संपर्क के कारण किसान निर्यात के अवसरों से भी हाथ धो बैठते हैं। निर्बाध अंतिम-मील कनेक्टिविटी बहुत मदद करेगी।

निष्कर्ष-

गति शक्ति देश के विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करेगी। जैसे-अगले पांच से छह वर्षों में देश भर में 16,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइनों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में गति शक्ति सहायक होगी। हालांकि, 2014 तक 27 साल में 15,000 किमी पाइपलाइन का निर्माण किया गया था। पिछले सात वर्षों में 9,000 किमी से अधिक रेलवे लाइनों को दोगुना कर दिया गया है जबकि 2014 से पहले पांच साल में 1,900 किमी पटरियों का दोहरीकरण हुआ। ■

भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित

गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेलवे का गौरव भी जुड़ गया है: नरेन्द्र मोदी

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन— देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड, देश का पहला पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन

गत 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश में रेलवे की कई अन्य पहलों को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें रेललाइन परिवर्तन और विद्युतीकृत उज्जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज बड़ी लाइन खंड, भोपाल-बरखेड़ा खंड में तीसरी रेल लाइन, रेललाइन परिवर्तन और विद्युतीकृत मथेला-निमाड़ खीरी बड़ी लाइन खंड और विद्युतीकृत गुना-ग्वालियर खंड शामिल है।

प्रधानमंत्री ने उज्जैन-इंदौर और इंदौर-उज्जैन के बीच दो नई मेमू रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेलवे का गौरव भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक रेलवे की परियोजनाओं के समर्पण को गौरवशाली इतिहास और समृद्ध आधुनिक भविष्य का संगम बताया। उन्होंने 'जनजातीय गौरव दिवस' की भी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता को लाभ होगा।

श्री मोदी ने कहा कि भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रही है। 6-7 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेलवे से पड़ता था, तो वो भारतीय रेलवे को ही कोसते हुए ज्यादा नजर आता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मीदें तक छोड़ दी थीं। लेकिन जब देश अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए ईमानदारी से जुटता है, तब सुधार आता है, परिवर्तन होता है, यह हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड, देश का पहला पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं कभी केवल एयरपोर्ट पर मिला करती थीं, वे सुविधाएं अब रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज का भारत न केवल आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि परियोजनाओं में देरी न हो और कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश के इस संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा।

> भारतीय रेल सिर्फ दूरियों को कनेक्ट करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति, देश के पर्यटन और तीर्थाटन को कनेक्ट करने का भी अहम माध्यम बन रही है

श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब रेल के बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को भी ड्रॉइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में सालों लग जाते थे। लेकिन आज भारतीय रेलवे नई परियोजनाओं की योजना बनाने में तत्परता दिखा रहा है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उन्हें समय पर पूरा भी करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल सिर्फ दूरियों को कनेक्ट करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति, देश के पर्यटन और तीर्थाटन को कनेक्ट करने का भी अहम माध्यम बन रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के इतने दशकों बाद पहली बार भारतीय रेल के इस सामर्थ्य को इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले रेलवे को टूरिज्म के लिए अगर उपयोग किया भी गया, तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सीमित रखा गया। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार आम लोगों को उचित राशि पर पर्यटन और तीर्थाटन का दिव्य अनुभव दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण सर्किट ट्रेन ऐसा ही एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने बदलाव की चुनौती को स्वीकार करने और उस पर काम करने के लिए रेलवे की सराहना की। ■

प्रधानमंत्री ने आरबीआई की दो अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों की शुरुआत की

'खुदरा प्रत्यक्ष योजना से अर्थव्यवस्था में सबके समावेश को ताकत मिलेगी'

खुदरा प्रत्यक्ष योजना अर्थव्यवस्था में सभी को शामिल करने की मजबूती देगी क्योंकि यह मध्यम वर्ग, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी छोटी बचत के साथ सीधे और सुरक्षित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का अवसर देगी

गत 12 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरबीआई की दो अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों— खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान उनके प्रयासों के लिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई जैसे संस्थानों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव का यह दौर 21वीं सदी का यह दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आरबीआई की भूमिका भी बहुत बड़ी है। मुझे विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।

आज जिन दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया, उनका उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से देश में निवेश के दायरे का विकास होगा और पूंजी बाजार तक पहुंच आसान हो जायेगी, वह निवेशकों के लिये अधिक आसान, अधिक

सुरक्षित बनेगा। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से देश के छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, एकीकृत लोकपाल योजना से बैंकिंग सेक्टर में 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' प्रणाली ने आज साकार रूप ले लिया है।

श्री मोदी ने इन योजनाओं की नागरिक केंद्रित प्रकृति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी वहां की शिकायत निवारण प्रणाली की ताकत होती है। एकीकृत लोकपाल योजना इस दिशा में बहुत आगे तक जाएगी। इसी प्रकार खुदरा प्रत्यक्ष योजना से अर्थव्यवस्था में सबके समावेश को ताकत मिलेगी, क्योंकि इससे मध्य वर्ग, नौकरीपेशा, छोटे व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों की छोटी बचतों के लिये सीधे तथा सुरक्षित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच बनेगी। सरकारी प्रतिभूतियों में अदायगी की गारंटी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे छोटे निवेशक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होंगे। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 24 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक (31 मार्च, 2026 तक) की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुकों को 3,054 करोड़ रुपये की वृत्तिका सहायता देने के लिए अपनी मंजूरी दी।

उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। एनएटीएस भारत सरकार की एक सुस्थापित योजना है, जिसने सफलतापूर्वक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है। इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुकों को क्रमशः 9,000/- रुपये और 8,000/- रुपये प्रति माह की वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) दी जाएगी।

सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय को मंजूरी दी, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय से लगभग 4.5 गुना अधिक है। अप्रेंटिसशिप में यह बढ़ा हुआ व्यय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अप्रेंटिसशिप को दिए गए महत्व के अनुरूप है। ■

'हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच देश के सामने रखा'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 नवंबर को पहले लेखा-परीक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस कार्यक्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएजी न केवल राष्ट्र के लेखा-खातों पर नज़र रखता है, बल्कि उत्पादकता और दक्षता में मूल्यवर्धन भी करता है, इसलिए लेखा-परीक्षण दिवस पर विचार-विमर्श और संबंधित कार्यक्रम हमारे सुधार व आवश्यक बदलाव का हिस्सा हैं। सीएजी एक ऐसी संस्था है, जिसका महत्व बढ़ गया है और इसने समय बीतने के साथ एक विरासत को विकसित किया है।

श्री मोदी ने कहा कि एक समय था, जब देश में लेखा-परीक्षण को आशंका और भय के साथ देखा जाता था। 'सीएजी बनाम सरकार,' यह हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज लेखा-परीक्षण को मूल्य संवर्धन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले देश में बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता की कमी के चलते तरह-तरह के गलत कामकाज होते थे। इसके परिणामस्वरूप बैंकों के फंसे कर्जे बढ़ते गये। उन्होंने कहा कि आपको अच्छी तरह पता है कि अतीत में फंसे हुए कर्जों को दरी के नीचे कवर करने का कार्य किया जाता था। बहरहाल, हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच देश के सामने रखा। हम समस्याओं को पहचानेंगे, तभी तो समाधान तलाश कर पायेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें 'सरकार सर्वम्' की सोच, यानी सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। उन्होंने लेखा-परीक्षकों को बताया कि यह मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के अनुसार किया जा रहा। संपर्क रहित प्रक्रिया, स्वचालित नवीनीकरण, व्यक्ति की उपस्थिति के बिना मूल्यांकन, सेवाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन– इन सभी सुधारों ने सरकार की अनावश्यक दखलंदाजी को खत्म कर दिया है। ■

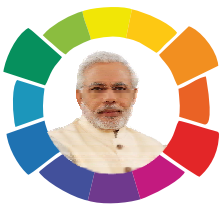

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

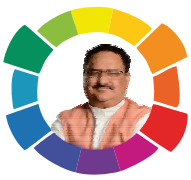

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भोपाल (मध्य प्रदेश) में 'जनजातीय गौरव दिवस' महासम्मेलन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का दौरा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

रांची (झारखंड) में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करता सीनेटर जॉन कोर्निन के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह